इकाई 6 विकास के सामाजिक सूचक

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 सामाजिक सूचकों के प्रकार

6.2.1 जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक (PQLI)

6.2.2 मानव विकास सूचकांक (HDI)

6.2.3 सामर्थ्य गरीबी माप (CPM)

6.3 शब्दावली

6.4 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.5 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा दिशा संकेत

6.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य आपको निम्नलिखित से अवगत कराना है :

- सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक;
- इनका ऐतिहासिक उदगम् तथा उनके विकास के पीछे उद्देश्य; और
- भारतीय अनुभव की कुछ अन्य विकासशील देशों, अफ्रीका तथा एशिया के अनुभव, से तुलना।

6.1 प्रस्तावना

अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम चाहेंगे कि आपको यह पता हो कि किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। इसका सबसे पहला सूचक तो देश की 'संवृद्धि' दर है। तेज़ संवृद्धि होने से ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के जीवन-स्तर में सुधार आएगा। लेकिन अनुभव से पता चलता है कि ऐसा हमेशा और स्वत: हो, आवश्यक नहीं है। संवृद्धि का अर्थ है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया भी नहीं है कि सभी की आय एक-समान बढ़े। आय के वितरण में असमानताएँ हो सकती हैं। इसके कारण यह आवश्यक नहीं कि आर्थिक संवृद्धि से आम लोगों के जीवन-स्तर में सुधार अवश्य ही हो। अत: आर्थिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में संवृद्धि दरों से अलग भी कुछ सोचना होगा।

'विकास' एक ऐसी अवधारणा है जो आर्थिक 'संवृद्धि' के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को भी अपने में शामिल करती है। यह एक बड़ी विस्तृत अवधारणा है। इसका मुख्य तत्त्व यह है कि देश के लोग अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया और साथ-साथ इन परिवर्तनों से होने वाले लाभों में मुख्य भागीदार बनें। उदाहरण के तौर पर, पिछले कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेज़ी से उन्नति की है। इस्पात पिण्ड (Steel Ingots) का उत्पादन 1950-51 से 1995-96 के बीच 15 लाख टन से बढ़कर 155 लाख टन हो गया। इसी अवधि में मशीनी औज़ार सूती कपड़ा मशीनों, सूती कपड़ा, चीनी, चाय, वनस्पति, सब में तेज़ी से वृद्धि आई। लेकिन, साथ साथ यह भी है कि 1993-94 में जनसंख्या का लगभग 36 प्रतिशत भाग न्यूनतम आय स्तर यानि गरीबी रेखा के नीचे था। इसका अर्थ यह हुआ कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को आर्थिक संवृद्धि के लाभ नहीं मिले। अत: विकास का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे मापों का प्रयोग हो जिससे यह मालूम पड़े कि विकास के लाभ लोगों तक पहुँचे भी हैं या नहीं।

गरीबी और असमानता के सूचकों की जाँच करना इस दिशा में पहला कदम है। क्रयशक्ति के दृष्टिकोण से इन सूचकों से हमें यह पता चलता है कि लोगों की जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या

प्राप्त हो रहा है। इसका एक और विकल्प है कि हम मुख्यत: स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सामाजिक सूचकों के आधार पर देश का मूल्यांकन करें। इससे यह पता चलेगा कि इन सेवाओं तक लोगों की कितनी पहुँच है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (Physical Quality of Life Index : PQLI) तथा मानव विकास सूचकांक (Human Development Index : HDI) इस वर्ग में आते हैं।

विकास के मूल्यांकन का एक और विकल्प है जिसका आधार विकास से यह अपेक्षा है कि परिवर्तन प्रक्रिया में लोगों की प्रमुख भागीदारी हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनमें एक न्युनतम सामर्थ्य (Capability) होना आवश्यक है। यही तीसरे विकल्प का आधार है जोकि सामर्थ्य गरीबी सूचकांक (Capability Poverty Index: CPI) के रूप में है, इस अवधारणा को मानव विकास रिपोर्ट (1996) में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। सामर्थ्य के तीन प्रमुख सूचक हैं : रोगों से बचाव, शिक्षा तथा स्वास्थ्य (पोषण के रूप में)। ये सूचक पहले बताए गए सूचकों से भिन्न हैं। पहले बताए गए सूचक यह मापते हैं कि लोगों की सेवाओं की तरफ कितनी पहुँच है जबकि ये 'सामर्थ्य सूचक' ये बताते हैं कि कितने लोग इन सेवाओं से वंचित रहे हैं। इस प्रकार सामर्थ्य गरीबी सूचकांक गरीबी मापने का एक वैकल्पिक तरीका है।

इस इकाई में मानव विकास के विभिन्न सूचकों की चर्चा की गई है। अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में इनकी स्थिति की चर्चा भी की गई है।

6.2 सामाजिक सूचकों के प्रकार

प्रति व्यक्ति 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (जी.एन.पी.) के विकास के माप के रूप में अपनाने में समस्याएँ आती हैं। कभी केवल यह नहीं है कि इससे आय की असमानताओं के कारण होने वाली समस्याओं का पता नहीं चलता बल्कि इसकी मुख्य आलोचना यह कहकर की जाती है कि जी.एन.पी. में वे गतिविधियाँ शामिल नहीं की जातीं जिनका बाज़ार में लेन-देन नहीं होता या फिर जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसका एक प्रमुख उदाहरण परिवार के सदस्यों द्वारा एक-दूसरे के लिए या स्वयं अपने लिए की गई सेवाएँ हैं। इससे दो अंतर पड़ते हैं। प्रथम, सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) का माप कम हो जाता है। दूसरे, समय के साथ-साथ इन सेवाओं का स्थान बाज़ार में बिकने वाली सेवाएँ लेने लगती हैं। उदाहरण के लिए, मरीज़ की देखभाल संबंधी सेवाएँ लीजिए। मरीज़ की देखभाल पहले प्राय: घर के लोग घर के अंदर ही करते थे। लेकिन अब यह सेवा बाज़ार में बिकती है। यह सेवा अब अस्पतालों, नर्सिंग होम में मिलती है। घर पर भी यह सेवा प्राप्त की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि जो सेवाएँ जी.एन.पी. में शामिल नहीं होती थीं, अब शामिल होने लगती हैं। इससे विभिन्न वर्षों में जी.एन.पी. की तुलना करने में कठिनाई आती है। विभिन्न देशों के बीच तुलना करने में भी यही कठिनाई आती है।

परिणामस्वरूप, विकास के माप के रूप में प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. की कमियों को दूर करने के प्रयत्न किए गए हैं। इसके विकल्प या फिर पूरक के रूप में संयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। इन सूचकों के दो वर्ग हैं- एक तो वे जो विकास के माप को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों के एक-दूसरे पर सामान्य प्रभाव के रूप में देखते हैं; दूसरे वे जो विकास को जीवन की गुणवत्ता के रूप में देखते हैं। इन सबका उद्देश्य देश के मूल क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है। ये वे क्षेत्र हैं जो जीवन-स्तर के विश्लेषण के अभिन्न अंग समझे जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे दो मूल क्षेत्र हैं।

संयुक्त सूचकों के प्रथम वर्ग के बारे में शुरू के अध्ययनों में से एक अध्ययन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था UNRISD (United Nations Research Institute on Social Development) ने 1970 में किया। इसमें विकास के सबसे उपयुक्त सूचकों का चुनाव किया गया। परिणामस्व रूप संयुक्त सामाजिक विकास सूचकांक का निर्माण हुआ। कुल 73 सूचकों की जाँच की गई। लेकिन उनमें से केवल 16 सूचक (9 सामजिक एवं 7 आर्थिक) चुने गए (देखिए तालिका 1) देखिए

तालिका 1 : संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास शोध संस्थान (UNRISD) द्वारा प्रयुक्त सामाजिक-आर्थिक विकास के मूल सूचकों की सूची

- जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
- 20 हज़ार और इससे अधिक आबादी वाले इलाकों में जनसंख्या का प्रतिशत

- प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पशु प्रोटीन का उपभोग
- प्राथमिक और सैकेण्डरी दाखिलों की संख्या
- व्यावसायिक दाखिलों का प्रतिशत
- प्रति कमरा व्यक्तियों की संख्या
- प्रति हज़ार जनसंख्या पर समाचार-पत्र चलन (circulation)
- बिजली, गैस, जल आदि सहित आर्थिक तौर पर सक्रिय जनसंख्या का प्रतिशत
- प्रति पुरुष कृषि श्रमिक द्वारा कृषि उत्पादन
- कृषि में बालिग पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत
- किलोवॉट (KW) प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग
- किलोग्राम प्रति व्यक्ति इस्पात उपभोग
- किलोग्राम कोयले के समान प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग
- विनिर्माण से उत्पन्न सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
- प्रति व्यक्ति विदेश व्यापाद (1960 में अमरीकी डॉलरों में)
- वेतन तथा मज़दूरी कमाने वालों का आर्थिक तौर पर सक्रिय कुल जनसंख्या का प्रतिशत

ये सूचक इनके आपसी सह-संबंधों के आधार पर चुने गए। इनके सह-संबंधों की श्रेणी के आधार पर इनके भार (Weights) चुने गए। इस विकास सूचकांक का सह-संबंध प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. की तुलना में व्यक्तिगत एवं सामजिक सूचकों से बहुत अधिक पाया गया। यह भी पाया गया कि विकास सूचकांक का प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. से सह-संबंध विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों में अधिक था। अध्ययन ने यह निष्कर्ष निकाला की 500 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के स्तर (1960 की कीमतें पर) तक सामाजिक विकास की गति आर्थिक विकास की गति की अपेक्षा अधिक रहती है।

सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों के परस्पर प्रभाव के रूप में विकास के माप का एक और अध्ययन इरमा एडलमेन (Irma Adelman) तथा सिंथिया मोरिस (Cynthia Morria) ने किया। इन्होंने इन पहलुओं के विभिन्न 40 चरों के आधार पर 74 देशों का वर्गीकरण किया। इस कारक विश्लेषण (factor analysis) का उपयोग सामाजिक एवं राजनीतिक चरों तथा आर्थिक विकास के स्तरों के बीच निर्भरता की जाँच करना था ताकि कोई माप विकसित हो सके। शोधकर्ताओं ने मूल चरों और आर्थिक विकास के बीच बहुत से सह-संबंध पाए।

कारक विश्लेषण के पीछे एक आदर्शी (normative) पूर्वधारणा है कि विकास का एक निश्चित पथ होता है। अत: विकासशील देशों का मूल्यांकन विकसित देशों के पथ के आधार पर किया जाता है। इस पूर्व-धारणा के पीछे कोई तर्कपूर्ण या ऐतिहासिक औचित्य नहीं लगता। इसके अतिरिक्त, प्रति हज़ार जनसंख्या के पीछे डॉक्टरों या अस्पताल में बिस्तरों की संख्या, या फिर प्राथमिक विद्यालयों में संख्या जैसी आगतों पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि विकास का मुख्य उद्देश्य तो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता जैसे 'उत्पादन' से है। यह कहना गलत नहीं होगा कि 'उत्पादन फलन' 'आगतों' को 'उत्पादन' में बदलता है। लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है। उदाहरण के तौर पर, प्रति हज़ार लोगों के पीछे डॉक्टरों की संख्या से यह पता नहीं चलता कि यह संख्या शहरों में कितनी है और गाँवों में कितनी और पिछड़े इलाकों में कितनी है और विकसित इलाकों में कितनी। इस आलोचना को ध्यान में रखते हुए बहुत से अध्ययन ऐसे संयुक्त सूचकों की तलाश में हैं जो विकास को अधिकांश जनसंख्या की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में या फिर जीवन की गुणवत्ता के रूप में मापें।

बोध प्रश्न 1

1) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) एक देश के जीवन-स्तर यानि लोगों के कल्याण का अनुपयुक्त माप क्यों कहा जाता है? (पाँच वाक्यों में उत्तर दीजिए।)

.....

.....

.....

.....

.....

6.2.1 जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक (The Physical Quality of Life Index-PQLI)

इस दिशा में एक जाना-माना प्रयत्न मोरिस डी. मोरिस (Morris D.Morris) द्वारा विकसित जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक (PQLI) था। एक साधारण संयुक्त सूचकांक बनाने के लिए तीन सूचकों का प्रयोग किया गया :

1) एक वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा

2) शिशु मृत्यु दर

3) साक्षरता दर।

हर सूचक का माप 1 से लेकर 100 तक है। 1 का अर्थ सबसे खराब प्रदर्शन तथा 100 का अर्थ सर्वोत्तम प्रदर्शन है। 77 वर्ष की जीवन प्रत्याशा को उच्चतम माप यानि 100 दिया गया (स्वीडन ने यह प्रत्याशा को सबसे कम यानी 1 का माप दिया गया [यह स्थिति गिन्नी (Guinea-Bissa) में थी]। इन दो सीमाओं के बीच प्रत्येक देश का श्रेणीकरण (ranking) किया गया। उदाहरण के तौर पर, 52 वर्ष की जीवन प्रत्याशा इसकी उच्चतम सीमा 77 वर्ष और न्यूनतम सीमा 28 वर्ष के मध्य में है। अत: इसे 50 का माप दिया गया। इसी तरह, शिशु मृत्यु दर की उच्चतम सीमा 9 प्रति हज़ार (1973 में स्वीडन में) तथा न्यूनतम सीमा 229 प्रति हज़ार [1950 में गेबन (Gabon)] निश्चित की गई। साक्षरता दर प्रतिशत में मापी जाती है, अत: जितना प्रतिशत उतना ही माप। एक देश को जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यूदर तथा साक्षरता दर 1 से लेकर 100 तक का माप देने के बाद, इन सबको एक-समान भार (weight) देते हुए इनकी भारित औसत लेकर देश का संयुक्त सूचकांक ज्ञात किया जाता है।

हालाँकि अध्ययन से पता चलता है कि कम प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. वाले देशों का पी.क्यू.एल.आई. कम और अधिक प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. वाले देशों का अधिक पी.क्यू.एल.आई. होता है, लेकिन फिर भी जी.एन.पी. तथा पी.क्यू.एल.आई. के बीच बहुत करीबी सह-संबंध नहीं था। कुछ देश जिनका प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. बहुत अधिक था उनका पी.क्यू.एल.आई. बहुत कम था, यहाँ तक कि सबसे गरीब देशों की औसत से भी कम। कुछ अन्य देश जिनका प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. बहुत कम था, उनका पी.क्यू.एल.आई. उच्च मध्यम आय वर्ग के देशों की औसत से अधिक था। तालिका-2 में विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति आयों एवं पी.क्यू. एल.आई. के आधार पर श्रेणीकरण किया गया है।

तालिका 2 : प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) एवं जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक (PQLI)

देश	प्रति व्यक्ति जी.एन.पी.(डॉलरों में)	पी.क्यू.एल.आई.
गेम्बिया	348	20
अंगोला	790	21
सूडान	380	34
तंजानिया	299	58
जिम्बाबवे	815	63
चीन	304	75

पाकिस्तान	349	40
भारत	253	42
श्रीलंका	302	82
सिंगापुर	5220	86
ताइवान	2503	87
सऊदी अरब	12720	40
इराक	3020	48
ब्राज़ील	2214	72

स्रोत : टोडारो, एम. पी. (1994): इकनॉमिक डिवलपमैंट पाँचवा एडीशन।

इससे पता चलता है कि प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. में वृद्धि से पहले ही जीवन की आधारभूत गुणवत्ता में सुधार प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. का ऊँचा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि जीवन की गुणवत्ता भी अधिक होगी। नोट कीजिए कि लगभग एक-समान प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. स्तर वाले कई ऐसे देश हैं जिनके पी.क्यू.एल.आई. में बहुत विभिन्नताएँ हैं जैसे अंगोला और ज़िम्बाबवे, चीन और भारत, तनजानियाँ और गेम्बिया, ताइवान और इराक। सऊदी अरब और श्रीलंका में तो यह विषमता बहुत अधिक है।

बोध प्रश्न 2

1) जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक के रूप में संयुक्त बनाने में प्रयुक्त तीन सूचक कौन-से हैं?

   क)

   ख)

   ग)

2) यदि यह माप हो तो देश का प्रदर्शन सर्वोत्तम माना जाता है :

   क) 100

   ख) 10

   ग) 1

   घ) 20

3) सभी देशों के जी.एन.पी. और पी.क्यू.एल.आई. में बहुत अधिक सह-संबंध होता है। यह सही है अथवा गलत?

   .....

   .....

4) पी.क्यू.एल.आई. के बारे में अधिक जी.एन.पी. वाले देशों और कम जी.एल.पी. वाले देशों का अनुभव पाँच वाक्यों में बताइए।

   .....

   .....

   .....

   .....

6.2.2 मानव विकास सूचकांक (Human Development Index)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme- UNDP) ने 1990 के प्रारंभ में अपनी मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report) की वार्षिक शृंखला में विकासशील एवं विकसित देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास के तुलनात्मक स्तरों के विश्लेषण का नवीनतम एवं महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न किया है। इन रिपोर्टों के पीछे मुख्य उद्देश्य मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) यानि HDI का निर्माण करना और इसमें सुधार लाना है। पी.क्यू.एल.आई. की तरह एच.डी.आई. का माप भी शून्य से लेकर 100 तक है। शून्य का अर्थ सबसे कम मानव विकास जबकि 100 का अर्थ सबसे अधिक मानव विकास है। यह विकास के तीन उद्देश्यों पर आधारित है:

1) **दीर्घायु,** जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापी जाती है।

2) **ज्ञान,** जोकि प्रौढ़ साक्षरता (दो-तिहाई भार) तथा स्कूल में पढ़ाई के औसत वर्ष (एक-तिहाई भार) के भारित औसत द्वारा मापा जाता है।

3) **आय,** जोकि समायोजित प्रति व्यक्ति आय द्वारा मापी जाती है। (यह समायोजन प्रत्येक देश की मुद्रा की क्रय-शक्ति में विभिन्नताओं और आय की तेज़ी से गिरती सीमांत उपयोगिता की पूर्व-धारणा के आधार पर किया जाता है।)

विकास के इन तीन मापों का प्रयोग करके एक जटिल फार्मूले द्वारा 1990 में 160 देशों के आँकड़ों के आधार पर, एच.डी.आई. ने सभी देशों को तीन वर्गों में बाँटा है :

निम्न मानव विकास (0.00 से 0.49 तक)

मध्यम मानव विकास (0.50 से 0.79 तक)

उच्च मानव विकास (0.80 से 1.00 तक)

यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एच.डी.आई. माप मानव विकास का सापेक्ष माप है, न कि निरपेक्ष। इसका केन्द्र विकास के परिणामों (दीर्घ आयु ज्ञान एवं आय) पर है न कि साधनों (यानि केवल प्रति व्यक्ति जी.एन.पी.) पर। इसके अतिरिक्त, जबकि पी.क्यू.एल.आई. स्वास्थ्य और शिक्षा के भौतिक सूचकों पर केंद्रित है, एच.डी.आई. में आय की भी भूमिका है क्योंकि इसमें समायोजित वास्तविक प्रति व्यक्ति आय एक सूचक के रूप में शामिल है। इस दृष्टि से विकास के सूचक में एच.डी.आई. को पी.क्यू.एल.आई. एवं प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. का सुधरा हुआ रूप कह सकते हैं।

तालिका 3 : मानव विकास सूचकांक (HDI) एवं सामर्थ्य गरीबी सूचकांक (CPM) की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से तुलना (1993)

देश	प्रति व्यक्ति वास्तविक जी.डी.पी.(PPP$)	एच.डी.आई.	सी.पी.एम.
संयुक्त राज्य अमरीका	24680	0.940	
स्वीडन	17900	0.933	
जापान	20660	0.938	
दक्षिण कोरिया	9710	0.886	8.6
पाकिस्तान	2160	0.442	19.3
भारत	1240	0.436	61.5
बंग्लादेश	1290	0.365	76.9
चीन	2330	0.609	17.5
इंग्लैण्ड	17230	0.924	
जर्मनी	18840	0.920	
ब्राज़ील	5500	0.796	10.0

तंजानिया	630	0.364	39.4
इराक	3413	0.599	39.9
अल्जीरिया	5570	0.746	49.5
कुवैत	21630	0.836	10.8

स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट (एच. डी. आर.) 1996।

तालिका-3 में कुछ चुने हुए देशों का मानव विकास सूचकांक यानी एच.डी.आई. दिया गया है और साथ में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (डॉलर में क्रय-शक्ति समानता) भी दिया गया है। इन दोनों की श्रेणियों में अंतर के आधार पर देशों की तुलना की गई है। सकारात्मक अंतर यह दिखाता है कि यदि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के स्थान पर एच.डी.आई. का प्रयोग करे तो एक देश की श्रेणी (rank) कितनी अधिक हो जाती है। नकारात्मक अंतर दिखाता है कि यह कितनी कम हो जाती है। स्पष्टत: एच.डी.आई. के लिए, या फिर पी.क्यू.एल.आई. जैसे संयुक्त सामाजिक सूचक के लिए यह एक नाजुक स्थिति है। यदि प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. अथवा जी.एन.पी. के स्थान पर एच.डी.आई. का प्रयोग करने से देशों के श्रेणीकरण में कोई विशेष अंतर नहीं आता, तो सामाजिक-आर्थिक विकास के माप में जी.एन.पी. का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है (जैसा कि कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है)। ऐसे में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सूचकों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

तालिका-3 में हम देखते हैं कि एच.डी.आई. माप पर आधारित श्रेणीकरण तथा प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. (PPP $) पर आधारित श्रेणीकरण में कोई प्रत्यक्ष समानता नहीं है। यह देखते हुए कि उच्च एच.डी.आई. वाले देशों की समायोजित प्रति व्यक्ति जी.डी.पी.भी ऊँची है, यह बात कुछ दिलचस्प लगती है। एक वर्ग के भीतर और कभी-कभी वर्गों के बीच हम यह पाते हैं कि कुछ देश जिनका एच.डी.आई. काफी अधिक है, उनकी प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। उदाहरण के तौर पर गिनी (0.306 की अपेक्षा तंजानिया का एच.डी.आई. (0.364) कुछ अधिक है हालाँकि गिनी की प्रति व्यक्ति आय तंजानिया से लगभग तीन गुना अधिक है। ऐसे कुछ उदाहरण और भी हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल जी.एन.पी. पर ही पूरा बल देने से अल्प-विकसित देशों में गरीबी या वंचन (deprivation) की समस्या को हल नहीं किया जा सकता।

हालाँकि एच.डी.आई. से विकास का विस्तृत रूप ज्ञात होता है, फिर भी निम्नलिखित पर ध्यान देना आवश्यक है :

1) इसकी रचना आंशिक तौर पर ऐसी राजनीतिक रणनीति से प्रेरित है जिसका उद्देश्य विकास के स्वास्थ्य और शिक्षा पहलुओं पर ध्यन केन्द्रित करना है;

2) तीन सूचक अच्छे तो है लेकिन आदर्श नहीं (उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की टीम चाहती थी कि पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पोषण स्तर उनका आदर्श स्वास्थ्य सूचक हो, लेकिन इसके बारे में आँकड़े उपलब्ध नहीं है);

3) राष्ट्रीय एच.डी.आई. से देश के भीतर इसमें असमानताओं के बारे में पता नहीं चल सकता।

4) प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. के साथ-साथ अन्य सामाजिक सूचकों को भी देखने का वैकल्पिक दृष्टिकोण अभी भी एक सम्मानित दृष्टिकोण है; और

5) यह भी याद रखना आवश्यक है कि यह सूचकांक सापेक्षिक विकास, न कि निरपेक्ष विकास का सूचकांक है। यदि सभी देशों में अपने भार के अनुसार सुधार आता है तो सबसे गरीब देशों को उनके अपने विकास का श्रेय नहीं मिलेगा।

6.2.3 सामर्थ्य गरीबी माप (The Capability Poverty Measure)

अमृत्य सेन (Amartya Sen) की सहायता से 'Human Development Report (1996)' ने एक बहुं-आयामी माप का आविष्कार किया। यह सामर्थ्य गरीबी सूचकांक (Capability Poverty Measure) यानी सी.पी.एम. (CPM) कहलाया। इस सूचकांक का केंद्र वंचन (deprivations) था न कि उपलब्धता। विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी उनके सामर्थ्य पर निर्भर होती है। सामर्थ्य स्वास्थ्य और शिक्षा पर निर्भर होता है। इसमें आधारभूत बात उत्तरजीविका (survival) तथा शिक्षा और विभिन्न सार्वजनिक या निजी

संसाधनों तक पहुँच की है। ऐसा विश्वास है कि यह सूचकांक उन लोगों का सही चित्र प्रस्तुत करता है जोकि इतने वंचित हैं कि उनके पास अपना जीवन सुधारने का कोई मौका नहीं है।

इस रिपोर्ट में मानव गरीबों को वंचनों के आधार पर मापा गया है :

1) जीवन से वंचन (सबसे कम विकसित देशों के लगभग एक-तिहाई लोग 40 वर्ष की आयु से अधिक जीवित रहने की आशा नहीं रखते);

2) बुनियादी (Basic) शिक्षा से वंचन (विशेषतौर पर लड़कियों की);

3) सुरक्षित जल सहित सार्वजनिक एवं निजी संसाधनों तक पहुँच से वंचन।

इन सबके सूचक ये हैं- कम वज़न वाले पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत, 15 वर्ष की आयु से अधिक अनपढ़ स्त्रियों का प्रतिशत तथा ऐसे जन्मों (births) का प्रतिशत जो कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों की सहायता से नहीं हुए। इस प्रकार, सी.पी.एम. सामर्थ्यताओं की कमी पर केंद्रित है, न कि देश की औसत सामर्थ्यताओं पर।

तालिका-3 में कम विकसित देशों के सी.पी.एम. के आँकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। यह नोट करना आवश्यक है कि सी.पी.एम. पर आधारित श्रेणीकरण एच.डी.आई. पर आधारित श्रेणीकरण से मेल नहीं खाता। जबकि यह नए सूचकांक की रचना आधार है, इससे इन क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप से संबंधित सिफारिशों पर भी प्रभाव पड़ता है। सरकारी हस्तक्षेप के उद्देश्यों में उचित फेर-बदल किया जाता है। प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. (अमरीकी डॉलर में) के हिसाब से भारत विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। कई गरीब अफ्रीकी देशों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। तालिका-2 से पता चलता है कि श्रीलंका, पाकिस्तान, इराक, गेम्बिया, अंगोला, तंजानिया, जिम्बाबवे, यहाँ तक कि सूडान का प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. भारत की अपेक्षा अधिक रहा है लेकिन पी.क्यू. एल.आई. के हिसाब से पाकिस्तान, गेम्बिया, अंगोला, सूडान की श्रेणी भारत की अपेक्षा नीचे है। अत: यह सुस्पष्ट है कि संवृद्धि और अपनी जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार के मामले में भारत का अनुभव एक मिला-जुला अनुभव रहा है।

तालिका-3 से पता चलता है कि दक्षिण कोरिया और कुवैत का एच.डी.आई. (क्रमश: 0.886 तथा 0.836) लगभग एक-सा है, जबकि दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय कुवैत का केवल 40 प्रतिशत के लगभग है। इससे यह संकेत मिलता है कि बेहतर मानव विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय का ऊँचा स्तर आवश्यक तो है लेकिन अपने आप में काफी नहीं है। चीन और इराक में लगभग यही स्थिति है। दोनों का एच.डी.आई. लगभग एक-समान है जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय इराक से 35 प्रतिशत कम है। हम कोई से भी माप लें, तालिका-3 से पता चलता है कि विश्व के अधिकतर देशों की तुलना में तीव्र संवृद्धि और अपनी जनसंख्या की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत को अभी बहुत दूर तक चलते रहना है।

बोध प्रश्न 3

1) UNRISD द्वारा विकसित सूचकांकों तथा एच.डी.आई. और पी.क्यू.एल.आई. सूचकांकों के बीच क्या अंतर है? इन सूचकांकों में वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) सामर्थ्य गरीबी सूचकांक का क्या महत्त्व है? यह एच.डी.आई. और पी.क्यू.एल.आई. से किस प्रकार भिन्न है? (चार पंक्तियों में उत्तर दीजिए।)

.....

.....

3) एच.डी.आई. और पी.क्यू.एल. आई. को लीजिए और बताइए कि इन दोनों विकास सूचकों के नीति संबंधी अर्थों में अंतर है? (पाँच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।)

.....

.....

.....

.....

.....

4) यू.एन.आर.आई.एस.डी. (UNRISD) पर आधारित सूचकांकों संबंधी नीति एच.डी.आई./पी.क्यू.एल. आई. पर आधारित सूचकांकों से संबद्ध नीतियाँ किस प्रकार अलग हैं? स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

6.3 शब्दावली

मानव विकास सूचकांक : जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजित प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर आधारित राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास को मापने वाला सूचकांक।

प्रति व्यक्ति आय : राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त।

शिशु मृत्युदर : प्रति 1000 नवजात शिशुओं की जन्म और उनके एक वर्ष की आयु के बीच मृत्यु।

जीवन-स्तर : जिस सीमा तक एक व्यक्ति, परिवार या व्यक्तियों का समूह अपनी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएँ पूरी कर सकता है। यदि वे केवल भोजन, आवास तथा वस्त्रों की केवल न्यूनतम आवश्यकता ही पूरी कर पाते हैं तो जीवन का स्तर काफी नीचा कहा जाता है। यदि वे विविध प्रकार के भोजन, आवास, वस्त्र तथा अन्य बातों जैसे अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और आराम पा सकते हैं तो इसे उच्च जीवन-स्तर कहा जाता है।

साक्षरता : पढ़ने और लिखने की योग्यता।

साक्षरता दर : 15 वर्ष से ऊपर जनसंख्या का वह भाग जो पढ़ना-लिखना जानता है। साक्षरता दरों को देश की विकास की स्थिति को बताने वाले कई आर्थिक और सामाजिक सूचकों में से एक माना जाता है।

कुपोषण : खराब स्वास्थ्य की वह स्थिति जो कि अनुपयुक्त खुराक के कारण होती है। खुराक को यहाँ औसत दैनिक प्रोटीन के उपयोग के रूप में मापा जाता है।

राष्ट्रीय आय : एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य।

जीवन की भौतिक गुणवत्ता : तीन सूचकों-प्रति हजार जनसंख्या के पीछे साक्षरता दर, शिशु मृत्युदर तथा डॉक्टरों की संख्या के औसत के रूप में एक संयुक्त सामाजिक सूचक।

सामाजिक सूचक : विकास के ग़ैर-आर्थिक कारक, जैसे प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, शिशु मृत्युदर तथा डॉक्टरों की संख्या।

दुष्चक्र : एक ऐसी स्थिति जिसमें विभिन्न कारक एक-दूसरे पर इस प्रकारन प्रभाव डालते हैं कि खराब स्थिति और भी खराब होती जाती है। जैसे गरीब देशों में कम आय के कारण उपभोग भी कम होता है, कम उपभोग से स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, श्रम उत्पादिता कम होती है और गरीबी की स्थिति निरंतर बनी रहती है।

कारक विश्लेषण : एक ऐसा विश्लेषण जिसमें विभिन्न चरों या सूचकों को उनके परस्पर महत्त्व के अनुसार भार दिए जाते हैं। इन सबके भारित मूल्यों को जोड़कर ऐसे मूल्य ज्ञात किए जाते हैं जिससे विश्लेषण हेतु एक समय पर विभिन्न देशों की और विभिन्न समयों पर एक देश की तुलना की जाती है।

6.4 कुछ उपयोगी पुस्तकें

EPW Research Foundation (1994): "Social Indicators of Development-II", *Economic and Political Weekly*, May 21, pp1300-1308.

Eswaran, Mukesh and Kotwal, Ashok (1994): "*Why Poverty Persists in India*", Oxford University Press, New Delhi, Ch.1, pp1-25.

Meier, G.M. (1991): "*Leading Issues in Economic Development*", Oxford University Press, Oxford, 4th Edition.

Todaro, Michael P (1994): "*Economic Development*", Longman Group, UK Limited, NY, Chs1, 3, 4, 5th Edition.

United Nations Development Programme (1996): "*Human Development Report*" 1996, Oxford University Press, New York.

World Bank (1991): "*World Development Report- Challange of Development*", Oxford University Press, New York.

6.5 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा दिशा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) भाग 6.2 देखिए।

बोध प्रश्न 2

1) क) एक वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा; ख) शिशु मृत्युदर; ग) साक्षरता

2) क) 100

3) गलत

4) उपभाग 6.3.1 पढ़िए।

बोध प्रश्न 3

1) पहली एक आदर्शी पूर्व-धारणा है कि विकास का एक निश्चित पथ होता है जबकि दूसरे में यह पूर्वधारणा नहीं है। दोनों सूचकांक इस बात पर केंद्रित हैं कि किस सीमा तक विकास के लाभ आम लोगों को मिलते हैं। (विवरण के लिए भाग 6.2 पढ़िए)।

2) भाग 6.3 पढ़िए।

3) दोनों सूचकों में आधारभूत अंतर यह है कि एच.डी.आई. में प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है जबकि पी.क्यू.एल.आई. में नहीं। इसी तरह, एच.डी.आई. आय पुनर्वितरण की आवश्यकता की बात करता है, जबकि पी.क्यू.एल.आई. नहीं।

4) पहला इस बात का समर्थन करेगा कि प्रति हजार जनसंख्या के पीछे डॉक्टरों की संख्या जैसी आधारभूत सेवाओं में आगतों की वृद्धि हो जबकि दूसरा इस बात पर केंद्रित है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति हो। इस प्रकार दूसरा, सेवा उपलब्ध न होने के पीछे कारणों को खोजेगा ताकि जीवन प्रत्याशा के रूप में अंतिम उत्पादन की प्राप्ति हो और इसके साथ जुड़ी समस्याओं का अध्ययन हो।